शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र,
दिनांक - 25-09-2020, वर्ग - BA-II

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विकास में योगदान (Development Impact of Industrial Development Bank of India)

भारत में औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछले पचास वर्षों (1964 ई० से 2014 तक) में देश के औद्योगिक विकास के लिए जो ~~वित्तीय~~ वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में दी गयी है वह अत्यन्त उत्साहवर्धक रही है। इसने देश के पूँजी बजार को गति प्रदान की तथा दीर्घकालीन पूँजी के लिए विकास बैंक अब देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है।

किन्तु देश के विकास में इसके योगदान का मूल्यांकन केवल इसके वित्तीय सहायता के आधार पर ही नहीं लगाया जाना चाहिए। वस्तुतः इसका योगदान इससे कहीं अधिक है। इसके द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव उत्पन्न किए हैं। इसके द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं में पाँच

लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

इन परियोजनाओं ने उत्पादन करके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है, सरकार को करो के रूप में पर्याप्त राजस्व इस परियोजना से प्राप्त हुआ है। इनकी उत्पादों के निर्यात से हमारी विदेशी मुद्रा की आय बढ़ी है अथवा आयात प्रतिस्थापन होने से विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

अपनी चहुंमुखी भूमिका के संदर्भ में अब ये बैंक दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं के कार्यकलापों का समन्वय करके, उनकी रीतियों एवं नीतियों को एक समान सूत्रों में बाँध सकने में सक्षम हो सका है। अतः अब विकास बैंक औद्योगिक परिवर्तन एवं विकास कार्य क्षेत्र में भारत की एक शीर्ष संस्था (Apex Institution) के रूप में कार्य कर रहा है।

IDBI के द्वारा सन 1986 में लघु उद्योग विकास निधि (Small Industry Development fund) की स्थापना की गयी। ताकि लघु उद्योग क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की अधिक

~~प्रवाह~~ प्रवाह हो सके और शीर्ष स्तर पर इस प्रकार की संस्थागत साख का उचित समन्वय किया जा सके।

इसके तत्वावधान में तीन प्रमुख कदम उठाये गए —

(i) भारत सरकार के सहयोग से IDBI द्वारा राष्ट्रीय इक्विटी कोष (National Equity fund) की स्थापना।

(ii) एक खिड़की सहायता योजना (Single window Assistance scheme)।

(iii) एशिया विकास बैंक (ADB) ने 100 मिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा ऋण से SFC के माध्यम से लघु औद्योगिक क्षेत्र की सहायता के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा 1988-89 का बजट प्रस्तुत करते समय घोषित निर्णय के अनुसार IDBI भारत के लघु उद्योग विकास बैंक गठन अपनी एक सहायक संस्था के रूप में कर चुका है। यह बैंक लघु उद्योग विकास ~~बैंक~~ तथा राष्ट्रीय इक्विटी कोष (NEF) दायित्व संभाल रहा है।

वित्तीय संस्थाओं के साधनों

का समर्थन देने का अभिप्राय से IDBI द्वारा राज्यों के वित्तीय निगमों तथा राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों (SIDC) के अंशो और ऋणपत्रों में पर्याप्त धन राशि का विनियोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन अन्य वित्तीय संस्थाओं में IDBI द्वारा पूँजी विनियोग किया गया है उनमें प्रमुख हैं— IFCI, SSIDC, Stock Holding Corporation of India, Discount & finance House of India, Shiping credit & Investment Co. of India Ltd. Technical Consultancy Organization आदि।

अनेक वित्तीय संस्थाओं के प्रबंध मंडलो में IDBI, प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अतः दीर्घकालीन वित्त (Term lending) के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्था के भाँति IDBI एक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

भारतीय औद्योगिक औद्योगिक विकास बैंक और नरसिंहम समिति → नरसिंहम समिति का मुख्य सिफारिश यह है कि बैंक और प्रत्यक्ष वित्त संस्थानों (Direct financing institution) के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर कुशलता

को उन्नत किया जा सकता है। इस दृष्टि से समिति विकास बैंक के कार्यभाग और कृत्यों में कुछ परिवर्तन लाना चाहती है।

समिति का सुझाव है कि बैंक को अपना प्रत्यक्ष वित्त प्रबंधन कार्य छोड़ देना चाहिए और अन्य संस्थान जैसे राज्य वित्तीय निगम, लघु उद्योग विकास बैंक आदि की भाँति सर्वोच्च प्रोन्नति का कार्य करना चाहिए। भारत सरकार ने नरसिंहम समिति के सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।